ढोल बजाने से नहीं खत्म होगी टीबी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जिले में गंभीर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस (एमडीआर) टीबी की दवाएं बीते ढाई महीने से खत्म हैं। प्रधानमंत्री के देश को 2025 में टीबी मुक्त करने की घोषणा कर देने से ही यह बीमारी खत्म नहीं हो जाएगी। इसके लिए सच्ची नीयत और ईमानदारी से टीबी को खत्म करने के प्रयास होने चाहिए।

ढिंढोरा पीटने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में देश से टीबी को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की घोषणा की थी, लेकिन उनकी डबल इंजन वाली सरकार के जिले फरीदाबाद में ही उनकी घोषणा जुमला साबित हो रही है। यहां मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस (एमडीआर) टीबी के मरीजों को बीते ढाई माह से दवा के लिए स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दवा नहीं मिलने से इनमें से अनेक टीबी मरीज गंभीर और घातक एक्टेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस (एक्सडीआर) टीबी के मुंह में पहुंच सकते हैं, कई मरीजों की असमय मृत्यु भी हो सकती है। लगता है कि घोषणावीर प्रधानमंत्री ने बिना जरूरी तैयारियों के ही अपने नाम पर टीबी मुक्त भारत अभियान की घोषणा कर दी थी। जिसके नतीजे दवाओं की कमी के रूप में सामने आ रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जून तक जिले में 113 एमडीआर मरीज थे जबकि छह मरीज एक्सडीआर थे। बताते चलें कि टीबी के वो मरीज जिन्होंने किसी कारण इलाज का कोर्स पूरा नहीं किया है या उनका इलाज बीच में ही छूट गया है, वह अधिक घातक और संक्रामक एमडीआर टीबी के शिकार हो जाते हैं। सामान्य टीबी मरीजों के मुकाबले एमडीआर मरीजों की दवा महंगी तो होती ही है साथ ही इसका कोर्स 18 से 24 महीने तक चलता है। यदि बीच में एक दिन भी दवा की खुराक नहीं ली गई तो पूरा कोर्स दोबारा करना पड़ता है। ऐसे में ढाई महीने तक मरीजों को दवा नहीं मिलना उनके लिए बहुत ही घातक है। टीबी के बैक्टीरिया मल्टी ड्रग्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं इससे यह दवा उन पर बेअसर हो जाती है। ऐसे मरीज एक्सटेंसिवली ड्रग्स रेजिस्टेंट (एक्सडीआर) में तब्दील हो जाते हैं। इनका इलाज बहुत ही मुश्किल और लंबा चलता है, इनमें बहुत ही कम लोग स्वस्थ हो पाते हैं अधिकतर की मृत्यु ही होती है।

बीके अस्पताल में एमडीआर टीबी की दवाएं लेने के लिए भटकते मरीज

एमडीआर और एक्सडीआर मरीज संक्रमण के लिहाज से भी अन्य लोगों के लिए सामान्य टीबी रोगियों से अधिक खतरनाक होते हैं, ऐसे में इनका पूर्ण और पर्याप्त इलाज होना बहुत ही जरूरी होता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दवा की व्यस्था करना तो दूर मरीजों को भगा रहे हैं।

दो-दो मंत्रियों के होते हुए जिले में टीबी की दवा लंबे समय से खत्म होना इन मंत्रियों ही नहीं केंद्र और राज्य की सरकारों के निकम्मेपन का सुबूत हैं। आयुष्मान योजना हो या किसी प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर से लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा सभी श्रेय लेने और फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं। दवा के बिना धीरे धीरे घुल कर मरने को मजबूर इन नागरिकों और वोटरों के हक में अधिकारियों से सवाल करते या सरकार से दवाओं की मांग करते इनमें से कोई नजर नहीं आ रहा।

बीके अस्पताल की ही तरह के हालात प्रदेश के अन्य जिलों के भी हैं लेकिन निकम्मे अधिकारियों की नीयत ही इन्हें दुरुस्त करने की नहीं है। अंबाला के सीएमओ दो करोड़ रुपये तक का लोकल परचेज कर सकते हैं, सीएमओ फरीदाबाद को भी चालीस लाख रुपये तक लोकल परचेज का अधिकार है। बावजूद इसके कोई भी अधिकारी मरीज और तीमारदारों के लाभ की नहीं सोचता। चालीस लाख हों या दो करोड़, खर्च तो होते हैं लेकिन कमीशनखोरी और बंदरबांट के लिए, न कि अस्पताल की सुविधाएं बढ़ाने, दवाओं की कमी को पूरा करने या मरीजों के हित के अन्य कार्यों के लिए।

बीके अस्पताल में खराब हालात सिर्फ टीबी विभाग के ही नहीं हैं। मॉर्चरी में शवों को संरक्षित रखने वाले डीप फ्रीजर अर्से से खराब पड़े हैं। शवों को, खासकर लावारिस शवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। पीएमओ और सीएमओ दोनों ही यहां बैठते हैं उन्हें इसकी जानकारी भी है। चालीस लाख रुपये तक लोकल परचेज का अधिकार होने के बावजूद सीएमओ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और सीएम खट्टर की डबल इंजन सरकार को चाहिए कि टीबी जुमलों से नहीं दवा से खत्म होगी, यदि डबल इंजन सरकार की नीयत सही है तो सभी जिलों में सरकारी अस्पतालों की कमियों को दुरुस्त कराएं और टीबी की पर्याप्त दवाएं समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पुलिस का मानवीय चेहरा

पुलिस का नाम जुबां पर आते ही मानस पटल पर एक नकारात्मक छवि उभर आती है, पर कभी-कभी इस खाकी वर्दी मे छुपा मानवीय चेहरा भी समाज के सामने आ जाता है। उज्जैन के महाकाल थाने के इंस्पेक्टर अजय वर्मा की खाकी वर्दी के नीचे छुपे संवेदनशील हृदय की जितनी तारीफ़ की जाए कम है।

मानवता को शर्मशार करने वाले उज्जैन हैवानियत कांड के विवेचक अजय वर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया है। अजय ने हैवानियत की शिकार बच्ची को गोद लेने का फैसला लिया हैं।

उन्होंने बच्ची की पढ़ाई-लिखाई समेत उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया है। बतौर अजय इलाज के दौरान मासूम की चीखों ने उन्हे झकझोर कर रख दिया और उनकी आंखें भर आई। अजय आपके निर्णय और आपकी भावनाओं और जज़्बे को सलाम !

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

भाजपाई पन्ना प्रमुख लग....

पेज एक का शेष

भाजपा को जिताने का संदेश देने आए थे। इस बीच अजरौंदा गांव निवासी राजेश शर्मा उर्फ राजू पुत्र खूबी राम ने खट्टर को काले कपड़े दिखाते हुए ''मोनू मानेसर को रिहा करवाओ, नूंह दंगे में मरने वाले वालों को शहीद का दर्जा दो'' के नारे लगाए। सीएम को काला झंडा दिखाने के कारण तुरंत ही पुलिस ने उसे दबोच लिया, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। इस्तेमाल कर बेदखल करने की परंपरा के वाहक सीएम खट्टर राजू को ऐसे नजरअंदाज कर गए जैसे वह भाजपा कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख हो ही नहीं। राजू के मुताबिक मोनू मानेसर हो या कोई अन्य 'गोरक्षक' सबने धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों से लड़ाई मोल ली। उनके पर्व-कार्यक्रमों में विघ्न डालने का भी काम किया। गोरक्षक और धर्म रक्षकों ने इतनी घटनाएं अंजाम दी हैं कि यदि सरकारी संरक्षण नहीं मिला तो वो कानून की गिरफ्त में तो आएंगे ही, समाज में इतनी दुश्मनी हो गई है कि जीना मुश्किल हो जाएगा।

पन्ना प्रमुख हों, भाजपा कार्यकर्ता या कट्टरपंथी तत्व, गोरक्षक मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के कारण इनमें सरकार के प्रति रोष और अविश्वास व्याप्त है। अधिकतर कट्टरपंथियों का मानना है कि खट्टर और सरकार ने ही इन दोनों की गिरफ्तारी कराई है, अगला नंबर किसी और गोरक्षक या धर्म रक्षक का हो सकता है। अब चुनाव आ रहे हैं तो सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए उन गोरक्षक, धर्म रक्षकों से किनारा कर रही है जो उसके लिए जान लेने पर उतारू रहते हैं, इन्हें सरकार ने बेसहारा छोड़ दिया है।

राजू की ही तरह स्वयंभू संस्था श्री सनातन धर्म महासभा व महिला एवं बाल विकास परिषद के चेयरमैन डॉ. तरुण अरोड़ा एडवोकेट भी खट्टर सरकार से नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार और हरियाणा गौसेवा आयोग गोसेवा का दिखावा मात्र करते हैं, सही मायने में सरकार व गौसेवा आयोग को न तो 'गौरक्षकों' के जीवन की कोई चिन्ता है और न ही गौमाता व गौवंश की। गौसेवा के नाम पर सनातन प्रेमियों को धोखे के सिवा कुछ और नहीं दिया जा रहा। हरियाणा सरकार व हरियाणा गौसेवा आयोग गौसेवकों व गौभक्तों से बड़े-बड़े वादे करते हैं परन्तु सभी खोखले ही नजर आते हैं। उन्होंने सड़क पर भूखे और बेसहारा घूम रहे गोवंश के प्रति चिंता जताते हुए इसके लिए सरकार, नगर निगम को दोषी करार दिया। सरकार को चेतावनी दी कि जब-जब गौमाता पर अत्याचार हुआ है तब-तब अत्याचार करने वालों का पतन हुआ है।

ये वही लोग हैं जो चंद महीने पहले तक सरकार के गुणगान किया करते थे लेकिन अब गोरक्षकों को सरकारी संरक्षण नहीं मिलने से इनमें बेचैनी साफ नजर आ रही है। कोई सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है तो कोई बैठक कर गोरक्षा नहीं करने वाली सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दे रहा है।